Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 09/September/2024 IJRAW: 2024; 3(10):129-133 Accepted: 25/October/2024

डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय स्वशासनः दौसा जिले में ई–पंचायत प्रणाली का मूल्यांकन

[*1]सुशील कुमार बसवाल

[*1]सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एसआरएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, सिकराय, दौसा, राजस्थान, भारत।

सारांश

यह शोध पेपर दौसा जिले में डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में ई–पंचायत प्रणाली के प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण प्रशासन में पारंपरिक प्रक्रियाओं में समय की देरी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय विकास और योजना प्रबंधन में सुधार की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। सिकराय तहसील और इसकी प्रमुख पंचायतें – सिकराय, पंचोली और पीलोडी – इस प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन का स्पष्ट उदाहरण हैं, जहाँ डिजिटल साधनों के माध्यम से योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन, परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण जैसी प्रक्रियाओं में तेजी, पारदर्शिता और प्रभावशीलता आई है। ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण जनता अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभा रही है, अपनी शिकायतें दर्ज कर रही है और योजनाओं की वास्तविक स्थिति जान पा रही है, जिससे स्थानीय स्वशासन में जनता की सहभागिता और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों बढ़ी हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल गवर्नेंस केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने का एक प्रभावी उपकरण भी है।

अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि ई–पंचायत प्रणाली की पूरी सफलता और दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिए तकनीकी अवसंरचना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, नियमित प्रशिक्षण और निरंतर तकनीकी समर्थन अत्यंत आवश्यक हैं। दौसा जिले का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि यदि इन उपायों को लागू किया जाए तो पंचायत स्तर पर योजनाओं का लाभ अधिक सटीक रूप से और समय पर वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों का प्रभावी विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रशासनिक निर्णयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी बनता है। यह शोध ग्रामीण प्रशासन में डिजिटल नवाचार के महत्व और स्थानीय स्वशासन में उसकी निर्णायक भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है और भविष्य में ई–पंचायत प्रणाली के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मुख्य शब्दः डिजिटल, पंचायत, स्वशासन, विकास, पारदर्शिता।

प्रस्तावना

राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित दौसा जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका नाम संस्कृत शब्द ''धौ–स'' से निकला है जिसका अर्थ है ''स्वर्ग के समान सुंदर''। इसे ''देव नगरी'' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां प्राचीन काल से ही देवस्थानों और धार्मिक स्थलों की समृद्ध परंपरा रही है। जयपुर से मात्र 55 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग–21 पर स्थित यह जिला प्राचीन कछवाहा वंश की पहली राजधानी रहा है। इस कारण यहां का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व और भी बढ़ जाता है। भीड़–भाड़ वाले शहरी जीवन से दूर, दौसा ग्रामीण राजस्थान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। जिले में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, पर्यटन विकास और

*Corresponding Author: सुशील कुमार बसवाल

ग्रामीण जीवन की वास्तविक झलक मिलती है, जिसके कारण यह क्षेत्र अध्ययन और शोध का आकर्षक केंद्र बनता जा रहा है।

वर्तमान समय में दौसा जिला न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी चर्चा में रहता है। हाल ही में यहां आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एल.ओ. एवं सुपरवाइजर के फ़ोन नंबर साझा किए गए, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, जिले में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, सहकारिता सदस्यता अभियान, कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों के विकास, पैनोरमा निर्माण तथा ई–गवर्नेंस परियोजनाओं जैसी पहलें हो रही हैं। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना और जिले के सर्वांगीण विकास को गति देना है। इस प्रकार दौसा एक ऐसा जिला है जहाँ अतीत की ऐतिहासिक धरोहर और वर्तमान की विकासपरक गतिविधियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में व्यावहारिक रूप में हुई, जबकि इसे संवैधानिक रूप देने का औचित्य 73वें संविधान संशोधन (1992) ने प्रदान किया। राजस्थान में इस व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी, जहां ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया और स्थानीय स्वशासन के प्रयोग ने ग्रामीण प्रशासन के स्वरूप को बदलने की नींव रखी। दौसा जिले में भी पंचायती राज प्रणाली ने इसी मॉडल का अनुसरण किया और ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और विकासात्मक कार्यों के लिए सशक्त बनाया। वर्तमान में ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से दौसा जिले की पंचायतें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कार्यों को संचालित कर रही हैं, जिसमें योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट प्रबंधन, शिकायत निवारण और ग्राम विकास योजनाएँ शामिल हैं। इस प्रणाली ने स्थानीय स्वशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने में मदद की है। दौसा का यह अनुभव यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ–साथ डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को सशक्त करना भी संभव है, जिससे ग्रामीण जनता को त्वरित और सुलभ सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

साहित्य समीक्षा

डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय स्वशासन पर किए गए शोधों से यह स्पष्ट होता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि ई–पंचायत जैसी पहलें ग्राम पंचायतों में योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन और शिकायत निवारण के कार्यों को सुव्यवस्थित करती हैं। Ministry of Panchayati Raj, Government of India और eGram Swaraj Portal की रिपोर्टों के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग पंचायत स्तर पर सेवाओं की समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ाने में प्रभावी साबित हुआ है। पूर्व शोधों ने यह भी संकेत दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधन की असमान उपलब्धता और तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ इन पहलों की पूर्ण क्षमता को सीमित करती हैं। राजस्थान में विशेष रूप से नागौर और दौसा जिलों के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जहां डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, वहां पंचायत स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों की गति और प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार हुआ।

राजस्थान में हुए कुछ शोध और सरकारी रिपोर्टें यह इंगित करती हैं कि ई–पंचायत प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता की भागीदारी, प्रशिक्षण और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। Rajasthan eGramSwaraj Reports और CAG Reports के अध्ययन में यह पाया गया कि ई–पंचायत के माध्यम से बजट पारदर्शिता, योजनाओं का निष्पादन, पंचायत विकास योजनाओं की निगरानी और शिकायत निवारण में सकारात्मक प्रभाव देखा गया। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, डिजिटल साक्षरता की असमानता और ग्राम पंचायत स्तर पर मानव संसाधन की सीमाएँ प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। वर्तमान शोध में दौसा जिले का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जिले की सामाजिक–आर्थिक विविधता, ऐतिहासिक महत्व और प्रशासनिक पहलुओं के कारण ई–पंचायत प्रणाली के प्रभाव और चुनौतियों को समझने हेतु उपयुक्त संदर्भ प्रदान करता है। इस प्रकार, साहित्य समीक्षा यह दर्शाती है कि भारत और राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस पहलें प्रभावी रही हैं, किंतु स्थानीय संदर्भ और अवसंरचना के अनुसार उनकी सफलता में भिन्नता देखने को मिलती है।

शोध समस्या

डिजिटल गवर्नेंस और ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इन पहलों के प्रभाव और कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। विशेष रूप से राजस्थान के दौसा जिले में डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन, योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन और शिकायत निवारण जैसी गतिविधियों के प्रभाव का मूल्यांकन अभी तक सीमित है। पंचायत स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग ग्रामीण जनता को त्वरित सेवाएँ प्रदान करने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तकनीकी अवसंरचना की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता, कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियाँ इन पहलों की प्रभावशीलता को

प्रभावित करती हैं। इस प्रकार यह शोध समस्या इस प्रश्न को केंद्र में रखती है कि दौसा जिले में ई–पंचायत प्रणाली ने स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक दक्षता को कितने प्रभावी रूप से सशक्त बनाया है और इसमें मौजूद बाधाओं और सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है।

दूसरे स्तर पर, यह शोध समस्या इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि ग्रामीण प्रशासन में डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक सहभागिता को कितना सशक्त बनाया जा रहा है। दौसा जिले की सामाजिक–आर्थिक विविधता, ग्राम पंचायतों की संख्या और ऐतिहासिक महत्व इसे अध्ययन के लिए उपयुक्त संदर्भ बनाते हैं। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किस हद तक ई–पंचायत परियोजनाएँ ग्रामीण विकास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में योगदान दे रही हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। शोध समस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से नीति निर्माताओं, जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल गवर्नेंस के क्रियान्वयन में व्यावहारिक सुझाव और सुधारात्मक दिशा–निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। यह अध्ययन दौसा जिले में ई–पंचायत के प्रभाव और चुनौतियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो भविष्य में अन्य जिलों और राज्यों में डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल के लिए भी मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

मुख्य विचार

डिजिटल गवर्नेंस और स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में मुख्य विचार इस शोध का केंद्रीय आधार हैं। यह खंड उन मूलभूत अवधारणाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है जिन पर दौसा जिले में ई–पंचायत प्रणाली का मूल्यांकन आधारित है। डिजिटल गवर्नेंस ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक, वित्तीय और विकासात्मक कार्यों को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की प्रक्रिया है, जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। स्थानीय स्वशासन, विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, ग्रामीण जनता को अपने विकास और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है। इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ई–पंचायत परियोजनाओं के माध्यम से कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी और त्वरित हुई हैं। इसके साथ ही, ग्रामीण प्रशासन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लाभ, चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ भी इस खंड में शामिल होंगी। मुख्य विचार का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कैसे तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ई–पंचायत प्रणाली स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाती है और ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।

1. डिजिटल गवर्नेंस की आवश्यकता

डिजिटल गवर्नेंस आज के समय में ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय की देरी, कागजी कार्यवाही की भारी मात्रा, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ अक्सर ग्रामीण जनता के लिए योजनाओं और सेवाओं तक पहुँच में बाधा डालती हैं। ग्रामीण पंचायतों के कार्य जैसे योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन, शिकायत निवारण, ग्राम विकास परियोजनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग, यदि केवल पारंपरिक माध्यमों से किए जाएँ तो उनका प्रभाव सीमित रहता है। डिजिटल गवर्नेंस इन प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित, त्वरित और पारदर्शी बनाती है। यह तकनीकी नवाचार केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों, उपलब्ध योजनाओं और पंचायत स्तर की गतिविधियों की जानकारी सीधे प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता यह देख सकती है कि कौन–सी योजना कब और किसे लाभ पहुँचा रही है, कौन से बजट का उपयोग कहाँ हो रहा है, और अपनी शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है। इस तरह से डिजिटल गवर्नेंस पंचायत प्रशासन और नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद, उत्तरदायी और पारदर्शी संबंध स्थापित करती है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दौसा जिले में, ई–पंचायत और अन्य डिजिटल परियोजनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी साधनों का प्रभाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता। डिजिटल गवर्नेंस ने ग्रामीण जनता की भागीदारी को सशक्त बनाया है और पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की है। पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना निगरानी, बजट नियंत्रण, लाभ वितरण और शिकायत समाधान में तेजी और सटीकता मिलती है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी को भी मजबूती मिलती है। इस प्रकार, डिजिटल गवर्नेंस स्थानीय स्वशासन को प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की आवश्यकता का प्रत्यक्ष उत्तर प्रस्तुत करती है। दौसा जिले का अनुभव इस तथ्य को पुष्ट करता है कि डिजिटल साधनों के उपयोग से ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है, जो पूरे राज्य और देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है।

2. ई–पंचायत प्रणाली की भूमिका

ई–पंचायत प्रणाली ने स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायतों के कार्यों में क्रांति ला दी है। पारंपरिक रूप से ग्राम पंचायतों के कार्य कागजी प्रक्रिया और व्यक्तिगत उपस्थिति पर निर्भर होते थे, जिससे योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और लाभ वितरण कई बार प्रभावित होता था। ई–पंचायत प्रणाली ने इस समस्या का समाधान करते हुए पंचायत प्रशासन के विभिन्न कार्यों को डिजिटल माध्यम से संचालित करना संभव बना दिया है।

इस प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन, परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण जैसे कार्य त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं। इसका एक बड़ा लाभ यह है कि पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी वास्तविक समय में योजनाओं की स्थिति, वित्तीय लेन–देन और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सटीक और जवाबदेह बन जाती है। इस तरह, ई–पंचायत प्रणाली न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाती है, बल्कि ग्राम पंचायतों के सभी विकासात्मक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

दूसरे स्तर पर, ई–पंचायत प्रणाली ग्रामीण जनता की भागीदारी और स्वशासन में उनकी सक्रिय उपस्थिति को भी सशक्त बनाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है, योजनाओं के लाभार्थी होने की स्थिति की जांच कर सकती है और स्थानीय विकास कार्यों में अपनी राय व्यक्त कर सकती है। इससे पंचायत और ग्रामीण समाज के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। राजस्थान के दौसा जिले में ई–पंचायत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों ने अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी रूप से निभाना शुरू कर दिया है और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचाने में सफलता मिली है। इस प्रकार, ई–पंचायत प्रणाली न केवल तकनीकी नवाचार का परिणाम है, बल्कि यह स्थानीय स्वशासन को सशक्त, उत्तरदायी और समावेशी बनाने का एक आवश्यक माध्यम बन चुकी है, जो ग्रामीण प्रशासन के आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है।

3. स्थानीय विकास और योजना प्रबंधन में ई–पंचायत का प्रभावः दौसा जिले का संदर्भ

दौसा जिले में ई–पंचायत प्रणाली ने स्थानीय विकास और योजना प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। पहले, ग्राम पंचायतों में योजनाओं का क्रियान्वयन और लाभ वितरण पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भर होते थे, जिससे देरी, भ्रष्टाचार और सूचना की कमी जैसी समस्याएँ आम थीं। ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से पंचायतों को वास्तविक समय में योजना संबंधी डेटा, बजट विवरण और परियोजना की प्रगति की जानकारी उपलब्ध होती है। इससे अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं को अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं। विशेष रूप से दौसा जिले की तहसीलें जैसे सिकराय, महुआ, बसवा और लालसोट ई–पंचायत के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल संरक्षण, सड़क निर्माण, स्कूल सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी प्रमुख विकास परियोजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचाने में सफलता मिली है।

इसके अलावा, इन तहसीलों की ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नागरिक सहभागिता और स्थानीय प्रशासन में उत्तरदायिता को भी बढ़ाया है। सिकराय और महुआ जैसी पंचायतों में ग्रामीण नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, योजनाओं की स्थिति जान सकते हैं और परियोजना निगरानी में सक्रिय रूप से सहयोग कर सकते हैं। बसवा और लालसोट जैसी पंचायतों में ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी वास्तविक समय में योजना प्रगति, वित्तीय लेन–देन और संसाधन आवंटन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सटीक और जवाबदेह बनी है। परिणामस्वरूप, दौसा जिले की ये तहसीलें डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और यह दर्शाती हैं कि ई–पंचायत प्रणाली स्थानीय विकास, योजना प्रबंधन और ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है।

4. पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार

ई–पंचायत प्रणाली ने ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन अक्सर धीमा और अपारदर्शी रहता था, जिससे नागरिकों को विकास कार्यों और योजना लाभों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता था। डिजिटल गवर्नेंस और ई–पंचायत प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब पंचायत स्तर पर वित्तीय लेन–देन, परियोजना प्रगति और योजना लाभार्थियों का विवरण वास्तविक समय में उपलब्ध है। नागरिक सीधे डिजिटल माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, योजनाओं की स्थिति जान सकते हैं और सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पारदर्शी और उत्तरदायी बन गई हैं और पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर जिम्मेदारी बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे।

सिकराय तहसील इस सुधार का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहाँ सिकराय, पंचोली और पीलोडी जैसी पंचायतों में ई–पंचायत प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन पंचायतों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बजट प्रबंधन, योजना निगरानी और लाभ वितरण प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। सिकराय और पंचोली पंचायतों में नागरिक सक्रिय रूप से डिजिटल माध्यम से शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और योजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे पंचायत प्रशासन की जवाबदेही बढ़ी है। पीलोडी पंचायत में भी ई–पंचायत के माध्यम से विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। इस तरह सिकराय तहसील की ये पंचायतें डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन और स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायिता और समावेशिता बढ़ाने का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

5. सुझाव और सुधार की संभावनाएँ

ई–पंचायत प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार और सुझाव आवश्यक हैं। सबसे पहले, तकनीकी अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अनियमित पहुँच और डिजिटल उपकरणों की कमी अभी भी कई पंचायतों में ई–पंचायत के उपयोग को सीमित करती है। इसके अलावा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी और दक्षतापूर्वक उपयोग कर सकें। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि ग्रामीण नागरिक ई–पंचायत प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इसके साथ ही, तकनीकी समर्थन और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है, जिससे समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके।

सिकराय तहसील और इसकी पंचायतोंकृसिकराय, पंचोली और पीलोडीकृके संदर्भ में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सुधारात्मक कदमों से स्थानीय प्रशासन की दक्षता और उत्तरदायिता और बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, योजना निगरानी और लाभ वितरण में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और अधिक व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक परियोजना का वास्तविक समय में मूल्यांकन संभव हो। पंचायत स्तर पर ग्रामीण जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय सूचना और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि नागरिक ई–पंचायत के माध्यम से योजनाओं और विकास गतिविधियों की निगरानी कर सकें। इसके अलावा, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी बनाई जा सकती है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार, सुझाव और सुधार की संभावनाओं को लागू करने से दौसा जिले में ई–पंचायत प्रणाली और स्थानीय स्वशासन की सफलता और प्रभावशीलता में और अधिक वृद्धि संभव है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ई–पंचायत प्रणाली ने दौसा जिले में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से ग्राम पंचायतों में योजना लाभ वितरण, बजट प्रबंधन, परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायिता बढ़ी है। सिकराय तहसील की पंचायतें – सिकराय, पंचोली और पीलोडी – इसके सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित हुई हैं। ग्रामीण जनता अब अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है और पंचायत प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है। इस प्रकार, ई–पंचायत प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई है, बल्कि ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थानीय स्वशासन की सशक्तता को भी सुनिश्चित किया है।

साथ ही, अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि डिजिटल गवर्नेंस के प्रभाव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता, प्रशिक्षण और तकनीकी समर्थन की आवश्यकता बनी हुई है। यदि इन सुधारों को लागू किया जाए, तो पंचायत स्तर पर प्रशासनिक निर्णय अधिक सटीक, योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी और जनता की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी। दौसा जिले का अनुभव यह दर्शाता है कि ई–पंचायत प्रणाली केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि स्थानीय विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायिता बढ़ाने का एक सशक्त उपकरण है। भविष्य में इसे और अधिक व्यापक स्तर पर लागू करके राजस्थान और अन्य राज्यों में ग्रामीण प्रशासन को और प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान सरकार, ''दौसा जिले की आधिकारिक वेबसाइट'', https://dausa.rajasthan.gov.in
2. Ministry of Panchayati Raj, Government of India, "E-Panchayat Mission Mode Project", New Delhi, 2015.
3. Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, "Digital India Programme: Impact on Local Governance", 2018.
4. Singh, R.K., "Digital Governance and Rural Development in Rajasthan", Jaipur: Rajasthan University Press, 2020.
5. Sharma, P., "E-Governance Initiatives in Indian Panchayats: A Case Study", Indian Journal of Public Administration, Vol. 66, No. 3, 2020.
6. Rajasthan Patrika, ''दौसा जिले में ई–पंचायत परियोजनाओं का प्रभाव'', Jaipur Edition, 12 March 2024.
7. Dainik Bhaskar, ''ग्रामीण विकास में डिजिटल गवर्नेंस की भूमिका'', Jaipur Edition, 8 August 2024.
8. Tiwari, A., "Role of E-Panchayats in Strengthening Local Self-Government", Journal of Rural Development Studies, Vol. 12, Issue 2, 2021.
9. Government of Rajasthan, "Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994", Jaipur, 1994.
10. 10. Agarwal, S., "ICT in Local Governance: Opportunities and Challenges", New Delhi: Sage Publications, 2019.
11. Meena, B.L., "Impact of Digital Governance on Rural Administration: Dausa District", Jaipur: University of Rajasthan, 2021.
12. Kumar, V., "E-Panchayat System and Transparency in Indian Rural Governance", International Journal of Public Administration, Vol. 44, No. 5, 2021.
13. Government of India, "Digital India Annual Report 2023", New Delhi, 2023.
14. Singh, A., "Local Governance and E-Governance in Rajasthan: Case of Dausa", Rajasthan Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1, 2022.
15. Rajasthan Government, "Annual District Development Report – Dausa, 2024", Jaipur, 2024.